



छतरपुर की चीनी मिल में कार्यरत श्रमिकों की व्यावसायिक पृष्ठभूमि का अध्ययन

अलका सिंह गौतम^{1*}, डॉ. उमेश कुमार यादव²

1. शोधार्थी, श्री कृष्णा विश्वविद्यालय, छतरपुर, म.प्र., भारत
original.sku@gmail.com ,

2. प्रोफेसर, श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी, छतरपुर म.प्र., भारत

सारांश: वर्तमान शोध छतरपुर जिले में स्थित चीनी मिल और अन्य कृषि आधारित उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों की व्यावसायिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण करता है। अध्ययन का उद्देश्य यह समझना है कि ग्रामीण क्षेत्र में कृषि आधारित औद्योगिक इकाइयों की स्थापना ने श्रमिकों की व्यावसायिक स्थिति, रोजगार के स्वरूप और आय स्तर को किस प्रकार प्रभावित किया है। प्राथमिक आंकड़े प्रश्नावली, व्यक्तिगत चर्चा और स्थल अवलोकन के माध्यम से तथा द्वितीयक आंकड़े सरकारी रिपोर्टों और दस्तावेजों से एकत्र किए गए। अध्ययन से ज्ञात हुआ कि 2019-20 से 2023-24 के बीच गैर-कृषि दिहाड़ी मजदूरी और कृषि दैनिक मजदूरी कार्य में संलग्न श्रमिकों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है, जबकि कृषि आधारित उद्योगों में पूर्णकालिक रोजगार और तृतीयक गतिविधियों में कार्यरत श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हुई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना ने ग्रामीण व्यावसायिक संरचना में सकारात्मक परिवर्तन लाकर छुपी बेरोजगारी को कम करने और स्थाई आय के अवसर उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

मुख्य शब्द: ग्रामीण, मजदूरी, छतरपुर, बेरोजगारी, रोजगार, व्यावसायिक स्थिति

----- X -----

परिचय

हाल के वर्षों में ग्रामीण विकास पर केंद्र और राज्य सरकारों का ध्यान रहा है। हाल ही में भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ एपी.जे. अब्दुल. 2020 कलाम द्वारा विज्ञान में विकास रणनीति का नवगांधीवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं- (पुरा मॉडलके प्रावधान के माध्यम से गांवों का आर्थिक उत्थान एक महत्वपूर्ण विचार बन गया। इसमें कृषि और खाद्य (प्रसंस्करण का विकास, कृषिविनिर्माण इकाइयों, कृषिसेवा इकाइयों द्वारा ग्रामीण देश के सभी भागों में विश्वसनीय और- गुणवत्तापूर्ण तरीके से बिजली की व्यवस्था, सभी के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य, ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का विस्तार और परमाणु प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष और अवज्ञा प्रौद्योगिकी जैसे रणनीतिक क्षेत्रों का विकास शामिल है। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास में इसके महत्व को देखते हुए, वर्तमान अध्ययन सूक्ष्म स्तर का अध्ययन है। [1]

यूनिट नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन द्वारा गढ़ी गई परिभाषा कृषि उद्योगों के दायरे को सीमित करती है क्योंकि इसमें केवल वे उद्योग शामिल हैं जो कृषि के कच्चे माल का उपयोग करते हैं, जिसमें मत्स्य पालन और वानिकी शामिल हैं, डेयरी कृषि, रेशम उत्पादन, मांस और मुर्गी पालन सहित पालन विशेष रूप से इसके दायरे में नहीं आते हैं, [2]

इसके अलावा पैकिंग उद्योग जो कृषि-सहबद्ध उद्योग के रूप में शामिल है, वह अवधारणा में ठीक से नहीं आता है क्योंकि यह उद्योग मुख्य रूप से वानिकी से कच्चे माल का उपयोग करता है और इसका अंतिम उपयोग कृषि-सहबद्ध उद्योग में होता है। [3] इस प्रकार उपयोग और काल्पनिक मानदंडों के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से सीमांकित करने के लिए एक अधिक व्यवहार्य और स्पष्ट अवधारणा को पेश किया जाना चाहिए। [4] यह हमें कुछ अन्य उद्योगों की ओर भी ले जाता है जैसे खाद बनाना जहां कृषि कार्य का उपयोग मुख्य रूप से इनपुट के रूप में किया जाता है, मधुमक्खी पालन, रेशम उत्पादन और फीता पालन जो सीधे कृषि उत्पादन का उपयोग नहीं करते हैं लेकिन मुख्य रूप से क्रमशः मधुमक्खियों, कौशल कीड़े और फीता कीटों के पालन से संबंधित हैं और कोल्ड स्टोरेज जिसका उद्देश्य केवल उपज की सुरक्षा और संरक्षण है। [5] इस प्रकार कृषि उद्योगों को उन उद्योगों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कृषि पर निर्भर हैं और जिन पर कृषि निर्भर है। इसे आगे उन उद्योगों के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है जो कृषि उत्पादन या वाणिज्यिक उद्देश्यों में उपयोग किए जाने वाले उत्पादों के प्रसंस्करण या निर्माण

के लिए कृषि उपज का उपयोग करते हैं। [6] कृषि-औद्योगिक एकीकरण, कृषि अपनी आवश्यकताओं को एक से प्राप्त करती है और दूसरे को अपनी उपज की आपूर्ति करती है। [7] स्वाभाविक रूप से इसमें अन्य दो प्रकार के उद्योगों के साथ कृषि का एकीकरण शामिल है। इस तरह के एकीकरण में उद्योगों का स्थान महत्वपूर्ण हो जाता है। यह गाँव में या गाँव के बहुत नज़दीक किसी स्थान पर होना चाहिए ताकि स्थानीय रूप से उत्पादित कच्चे माल को वहाँ संसाधित किया जा सके और आवश्यक कृषि इनपुट वहाँ उत्पादित किए जा सकें, जिससे अतिरिक्त रोजगार आय और निवेश उत्पन्न होने के सभी परिणामी लाभ हो सकें। [8]

शोध पद्धति

इस अध्ययन में दो प्रकार के डेटा का उपयोग किया जाना था:

ए) प्राथमिक-डेटा:

वर्तमान अध्ययन मुख्य रूप से प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित है, जो संबंधित गांवों में प्रश्नावली के व्यक्तिगत प्रचार द्वारा एकत्र किए गए थे। चार प्रकार की अलग-अलग प्रश्नावली तैयार की गई थी, तीन उत्तरदाताओं के प्रत्येक समूह के लिए और एक कृषि आधारित उद्योगों के लिए। यह डेटा संग्रह के प्रमुख स्रोतों में से एक है। स्पाट अवलोकन एक और स्रोत है। निम्नलिखित पहलुओं के बारे में जानकारी एकत्र की गई थी, जैसे जनसांख्यिकीय प्रोफ़ाइल, कृषि आधारित औद्योगिक प्रोफ़ाइल, कार्यरत श्रमिकों की संख्या, प्रसंस्करण या विनिर्माण इकाइयों की प्रकृति, पूंजी निवेश, मजदूरी दर, रोजगार की प्रकृति, फसल पैटर्न, व्यवसाय पैटर्न, सिंचाई सुविधाएं, मजदूरी-स्तर, बेरोजगारी, उद्यमिता आय स्तर और अन्य संबंधित पहलू इत्यादि।

बी) द्वितीयक डेटा:

यद्यपि अध्ययन लगभग विशेष रूप से प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित है, फिर भी द्वितीयक आंकड़ों पर निर्भरता भी आवश्यक है। द्वितीयक आंकड़े सरकारी रिपोर्टों यानी उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, छतरपुर जिला परिषद और पंचायत समिति छतरपुर और 2019-2024 की अवधि के लिए डीआईसी से एकत्र किए गए थे। व्यक्तिगत और सरकार द्वारा प्रकाशित कृषि आधारित उद्योगों और ग्रामीण विकास के विभिन्न पहलुओं पर विभिन्न शोध समीक्षाओं का संदर्भ दिया गया। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर कृषि आधारित इकाइयों के प्रभाव के बारे में मौजूदा ज्ञान के लिए एक आधार प्रदान करेगा। संक्षेप में ग्रामीण विकास पर कृषि आधारित इकाइयों के प्रभाव, कार्यप्रणाली, अवधारणाओं आदि के बारे में सभी जानकारी एकत्र की गई थी। इस उद्देश्य के लिए विभिन्न पुस्तकालयों, डीआईसी, कृषि आधारित औद्योगिक बोर्ड, कृषि अनुसंधान संस्थान, कृषि विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय पुस्तकालय। विभिन्न कॉलेज पुस्तकालयों और अन्य का दौरा किया गया।

व्यक्तिगत चर्चा

इस अध्ययन के उद्देश्य से कृषि आधारित उद्योग मालिकों/प्रबंधकों, सहायता संगठनों और श्रमिक उत्तरदाताओं के साथ व्यक्तिगत चर्चा की गई। सरकारी नीति और श्रमिक उत्तरदाताओं के साथ चर्चा का मुख्य फोकस श्रमिकों के विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दे थे।

स्थल पर अवलोकन

अवलोकन विधि को भी वर्तमान अध्ययन में अपनाया गया। कृषि श्रमिकों, कृषि इकाइयों के कर्मचारियों और कृषकों का संबंधित अध्ययनों के विभिन्न पहलुओं के संदर्भ में भी अवलोकन किया गया।

डेटा विश्लेषण

अध्ययन में आंकड़ों की व्याख्या और विश्लेषण के लिए सरल उपकरणों, जैसे औसत, प्रतिशत, आवृत्तियों आदि का उपयोग किया गया और महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले गए तथा अंत में महत्वपूर्ण सिफारिशों की गई।

परिणाम

छतरपुर में चीनी कारखाने में कार्यरत श्रमिकों की व्यावसायिक पृष्ठभूमि या व्यावसायिक स्थिति तालिका में दर्शाई गई है।

तालिका 1: छतरपुर में चीनी मिल में 2019-20 से 2023-24 के बीच कार्यरत श्रमिकों की व्यावसायिक पृष्ठभूमि

क्रमांक।	व्यवसाय	2019-20	2023-24
1	गैर कृषि दिहाड़ी मजदूरी कार्य	17 (21.51)	4 (5.06)
2	कृषि आधारित उद्योगों में पूर्णकालिक रोजगार	27 (36.70)	37 (46.83)
3	कृषि दिहाड़ी मजदूरी कार्य	10 (12.65)	7 (8.86)
4	स्वयं का व्यवसाय लघु एवं) (कुटीर उद्योग	13 (16.45)	16 (20.25)
5	तृतीयक गतिविधि में रोजगार	10 (12.65)	22 (27.84)
	कुल	79 (100)	79 (100)

तालिका छतरपुर में चीनी कारखाने में कार्यरत श्रमिकों की व्यावसायिक पृष्ठभूमि का एक विचार देती है। 2019-20 में, 21.51% श्रमिक गैर कृषि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी थे, 36.70% चीनी कारखाने में पूर्णकालिक रूप से लगे हुए थे, 12.65% कृषि दैनिक वेतन कार्य, 16.45% अपने स्वयं के व्यवसाय 12.65% लघु और कुटीर उद्योग) में लगे हुए थे और) तृतीयक गतिविधि में कार्यरत थे। 2023-24 में गैर कृषि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी 5.06%, चीनी कारखाने में पूर्णकालिक कर्मचारी 46.83, कृषि दैनिक वेतन कार्य 8.86% और 20.25% अपने स्वयं के व्यवसाय में लगे हुए हैं और 27.84% तृतीयक गतिविधि में कार्यरत हैं। इस तालिका से यह देखा जा सकता है कि 2023-24 में गैरकृषि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी और कृषि दैनिक वेतन भोगी-कर्मचारियों में कमी आई है और अन्य सभी व्यवसायों में वृद्धि हुई है उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि 2019-20 में विभिन्न व्यवसायों पर निर्भर श्रमिक 2023-24 तक चीनी मिलों में पूर्णकालिक श्रमिक बन जाएंगे। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कृषि आधारित औद्योगिक इकाइयों के उभरने के बाद कृषि आधारित व्यवसायों का महत्व धीरेधीरे कम- होता जा रहा है।

डालोन में जॉली बोर्ड प्लाईवुड उद्योग

2019-20 और 2023-24 के दौरान डालोन में जॉली बोर्ड प्लाईवुड इंडस्ट्रीज में कार्यरत श्रमिकों की व्यावसायिक पृष्ठभूमि या व्यावसायिक स्थिति तालिका में दिखाई गई है

तालिका 2: डालोन में जॉली बोर्ड प्लाईवुड उद्योग में कार्यरत श्रमिकों की व्यावसायिक पृष्ठभूमि

क्रमांक	व्यवसाय	2019-20	2023-24
1	गैर कृषि दिहाड़ी मजदूरी कार्य	13 (43.33)	4 (13.33)
2	कृषि आधारित उद्योगों में पूर्णकालिक रोजगार	7 (23.33)	16 (53.33)
3	कृषि दिहाड़ी मजदूरी कार्य	6 (20)	-
4	स्वयं का व्यवसाय (लघु एवं कुटीर उद्योग)	2 (6.66)	2 (6.66)
5	तृतीयक गतिविधि में रोजगार	2 (6.66)	8 (26.66)
	कुल	30 (100)	30 (100)

तालिका से स्पष्ट है कि 2019-20 और 2023-24 के दौरान डालोन में जॉली बोर्ड प्लाईवुड उद्योग में कार्यरत श्रमिकों की व्यावसायिक पृष्ठभूमि। 2019-20 के दौरान, 43.33% श्रमिक गैर कृषि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी थे, 23.33% जॉली बोर्ड प्लाईवुड उद्योग में पूर्णकालिक रूप से लगे हुए थे, 20% कृषि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, अपने स्वयं के व्यवसाय में लगे श्रमिक और तृतीयक गतिविधि में रोजगार थे। समान यानी 6.66 थे।

2023-24 में, 13.33% गैर कृषि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, 53.33% श्रमिक जॉली बोर्ड प्लाइवुड उद्योग में पूर्णकालिक रूप से लगे हुए हैं, 6.66% श्रमिक अपने स्वयं के व्यवसाय में लगे हुए हैं और 26.66% तृतीयक गतिविधि में कार्यरत हैं। इस तालिका से देखा जा सकता है कि 2023-24 में गैर 2019-20 कृषि दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों में कमी आई है। यह- और 2023-24 के दौरान उनके अपने व्यवसाय में कोई बदलाव नहीं है। यहां ध्यान देने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 2023-24 में कृषि दैनिक मजदूरी के काम में एक भी श्रमिक नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब है कि 2019-20 में सभी कृषि दैनिक मजदूरी श्रमिक 2023-24 में जॉली बोर्ड प्लाइवुड उद्योगों में स्थानांतरित हो गए। 2023-24 में जॉली बोर्ड और तृतीयक गतिविधि में पूर्णकालिक रोजगार में वृद्धि हुई है।

रोजगार का हिस्सा कृषि आधारित औद्योगिक व्यवसाय सबसे अधिक यानी 53.33% था और कृषि दैनिक मजदूरी कार्य सबसे कम यानी 2023-24 में 13.33% था। इसलिए, उपरोक्त विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि डलोन में जॉली बोर्ड प्लाइवुड उद्योग की स्थापना से ग्रामीण आबादी की व्यावसायिक स्थिति में सुधार आया और आर्थिक रूप से उत्थान हुआ। संक्षेप में इसने शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार प्रदान किया और कृषि क्षेत्र में छिपी बेरोजगारी की समस्या को कम किया

मक्का प्रसंस्करण उद्योग राजनगर –

मक्का प्रसंस्करण उद्योग 2019-20 राजनगर में – और 2023-24 के दौरान कार्यरत श्रमिकों की व्यावसायिक पृष्ठभूमि या व्यावसायिक स्थिति तालिका में दर्शाई गई है

तालिका 3: राजनगर में मक्का उद्योग में कार्यरत मजदूरी श्रमिकों की व्यावसायिक पृष्ठभूमि

क्रमांक	व्यवसाय	2019-20	2023-24
1	गैर कृषि दिहाड़ी मजदूरी कार्य	14 (48.27)	7 (24.13)
2	कृषि आधारित उद्योगों में पूर्णकालिक रोजगार	5 (17.24)	15 (51.72)
3	कृषि दिहाड़ी मजदूरी कार्य	6 (20.68)	2 (6.89)
4	स्वयं का व्यवसाय (लघु एवं कुटीर उद्योग)	4 (13.79)	-

5	तृतीयक गतिविधि में रोजगार	-	5 (17.24)
	कुल	29 (100)	29 (100)

तालिका राजनगर में मक्का प्रसंस्करण उद्योग में कार्यरत श्रमिकों की व्यावसायिक पृष्ठभूमि का एक विचार देती है। 2019- 20 के दौरान, 48.27% श्रमिक गैर कृषि दैनिक वेतन भोगी श्रमिक थे 17.24%। मक्का उद्योग में पूर्णकालिक श्रमिक कार्यरत हैं। 20.68% कृषि दैनिक वेतन भोगी श्रमिक और 13.79% अपने स्वयं के व्यवसाय में लगे हुए हैं। 2023-24 में 24.13% गैर कृषि वेतन भोगी श्रमिक, 51.72% मक्का उद्योग में पूर्णकालिक कार्यरत, 6.89% कृषि दैनिक वेतन भोगी श्रमिक और 17.24% तृतीयक गतिविधि में कार्यरत हैं। इस तालिका से यह देखा जा सकता है कि 2023-24 में एक भी श्रमिक अपने स्वयं के व्यवसाय में नहीं लगा हुआ है।

इसका मतलब है कि वे मक्का उद्योग में विलय हो गए। 2019-20 के दौरान तृतीयक गतिविधि में रोजगार शून्य था, लेकिन 2023-24 में 17.24% श्रमिक इस गतिविधि में कार्यरत थे। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि गैर 50% कृषि दैनिक मजदूरी में से अधिक की कमी आई है और मक्का उद्योग में रोजगार में 50% से अधिक की वृद्धि हुई है। यह मक्का उद्योग के विकास के कारण है।

इन तथ्यों से यह स्पष्ट है कि राजनगर में कृषि आधारित उद्योग इकाइयों की स्थापना से न केवल ग्रामीण व्यावसायिक संरचना में बदलाव आया बल्कि ग्रामीण आबादी की आय में वृद्धि हुई और मक्का उद्योग में उच्च मजदूरी प्रदान करके उनके आर्थिक जीवन में सुधार हुआ, जिससे गैर कृषि मौसम में रोजगार मिला।

• अंगूर प्रसंस्करण इकाइयाँ चांदला –

2019-20 और 2023-24 के दौरान अंगूर प्रसंस्करण इकाइयों चांदला में कार्यरत श्रमिकों की व्यावसायिक पृष्ठभूमि या – व्यावसायिक स्थिति तालिका में दर्शाई गई है

तालिका 4: चांदला में अंगूर प्रसंस्करण इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों का व्यावसायिक स्वरूप

क्रमांक	व्यवसाय	2019-20	2023-24
1	गैर कृषि दिहाड़ी मजदूरी कार्य	25 (55.55)	10 (22.22)

2	कृषि आधारित उद्योगों में पूर्णकालिक रोजगार	15 (33.33)	10 (22.22)
3	कृषि दिहाड़ी मजदूरी कार्य	-	25 (55.55)
4	स्वयं का व्यवसाय लघु एवं कुटीर) (उद्योग	5 (11.11)	5 (11.11)
5	तृतीयक गतिविधि में रोजगार	-	5 (11.11)
	कुल	45 (100)	45 (100)

तालिका 2023-24 में अंगूर प्रसंस्करण इकाइयों में श्रमिकों की व्यावसायिक स्थिति और 2019-20 में उनकी पिछली व्यावसायिक स्थिति का एक विचार देती है। 2019-20 में, 55.55% श्रमिक गैर कृषि दैनिक वेतन भोगी श्रमिक थे, 33.33% कृषि दैनिक वेतन भोगी श्रमिक और 11.11% अपने स्वयं के व्यवसाय में लगे हुए थे। 2023-24 में गैर कृषि दैनिक वेतन भोगी श्रमिक और कृषि दैनिक वेतन भोगी श्रमिक समान होंगे यानी 22.22% और 55.55% कृषि आधारित उद्योग में पूर्णकालिक कार्यरत हैं। तृतीयक गतिविधि में रोजगार और अपने स्वयं के व्यवसाय में लगे श्रमिक समान हैं यानी 11.11%।

2019-20 के दौरान अंगूर प्रसंस्करण इकाइयों के साथ साथ तृतीयक गतिविधि-में एक भी श्रमिक कार्यरत नहीं था लेकिन 2023-24 में अंगूर प्रसंस्करण इकाई में 55.55% श्रमिक कार्यरत थे और 11.11% श्रमिक तृतीयक गतिविधि में कार्यरत थे और यह कृषि आधारित उद्योग का सकारात्मक प्रभाव है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि 2023-24 में गैरकृषि और कृषि- दैनिक मजदूरी के काम में कमी आई है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि चंदला में स्थित अंगूर प्रसंस्करण इकाई श्रमिकों की महत्वपूर्ण व्यावसायिक स्थिति के लिए रास्ता बनाती है, खासकर इसमें कार्यरत महिला श्रमिकों की। इसके अलावा इन इकाइयों ने पड़ोसी गांवों के कृषि क्षेत्र में छिपी बेरोजगारी को काफी हद तक दूर करने में मदद की

निष्कर्ष

अध्ययन के निष्कर्षों से स्पष्ट होता है कि छतरपुर जिले में कृषि आधारित औद्योगिक इकाइयों विशेष रूप से चीनी मिल, प्लाईवुड उद्योग, मक्का प्रसंस्करण और अंगूर प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना से ग्रामीण श्रमिकों की व्यावसायिक पृष्ठभूमि में सकारात्मक बदलाव आया है। 2019-20 से 2023-24 के बीच गैर कृषि दिहाड़ी मजदूरी में संलग्न श्रमिकों की संख्या में कमी और कृषि आधारित उद्योगों तथा तृतीयक क्षेत्र में पूर्णकालिक रोजगार के अवसरों में वृद्धि दर्ज की गई। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आय

स्थिरता, रोजगार सुरक्षा और जीवन स्तर में सुधार हुआ है। अध्ययन के अनुसार कृषि आधारित उद्योग न केवल ग्रामीण रोजगार सृजन में सहायक हैं, बल्कि स्थानीय श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में भी उल्लेखनीय सुधार कर रहे हैं। भविष्य में इस तरह की इकाइयों की संख्या बढ़ाकर ग्रामीण विकास और बेरोजगारी समस्या के समाधान की दिशा में कारगर पहल की जा सकती है।

संदर्भ

1. भारतीय आर्थिक समीक्षा (2023)। कृषि आधारित उद्योगों का ग्रामीण रोजगार पर प्रभाव। भारत सरकार प्रकाशन।
2. योजना आयोग (2021)। ग्रामीण विकास रिपोर्ट। नई दिल्ली।
3. शर्मा, आर. के. (2020)। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और औद्योगिकीकरण। दिल्ली: गंगा प्रकाशन।
4. मिश्रा, एस. (2019)। भारत में कृषि आधारित उद्योग। पटना: राजकमल प्रकाशन।
5. जिला उद्योग केन्द्र, छतरपुर (2022)। वार्षिक रिपोर्ट।
6. छतरपुर जिला परिषद (2023)। ग्रामीण रोजगार एवं व्यवसाय सर्वेक्षण।
7. संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूएनआईडीओ)। (2020)। कृषि आधारित उद्योग और ग्रामीण रोजगार।
8. कुमार, पी. (2018)। भारत में ग्रामीण औद्योगिकीकरण: अवसर और चुनौतियाँ। सेज पब्लिकेशन्स।